सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं पर बराबर नजर रखती है और इसकी रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाती है।

Sale of Military Equipments to Pakistan By USA

1620. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:
SHRI RAMDAS AGARWAL:
SHRI ANANT RAM JAISWAL:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have conveyed to the U.S. its strong opposition to the proposal of the Clinton Administration to transfer to Pakistan million dollars of military equipments; and

(b) how Government propose to react to neutralise the transfer of military equipments like P-3C Orion reconnaissance aircraft and anti-ship harpoon missiles by circumventing the Pressler Amendment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTERY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHID): (a) Yes, Sir.

(b) Government of India are closely monitoring developments in this regard and remain committed to taking all steps necessary to meet India's security requirements.

Time Bound Plan to Electrify Rail Lines in Gujarat

1621. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there is any time bound plan to electrify all the rail lines in Gujarat State;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the total kilometres electrified/ under electrification in the State at present?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF) (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) 651 Route Kms.

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक का वितरण

1622. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण व्यवस्था की अंतिम पुनरीक्षा कब की है;

(ख) इस पुनरीक्षा का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) सरकार ने इस पुनरीक्षा के आधार पर प्राप्त परिणामों के संबंध में क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) देश में डाक पारेक्षण और वितरण प्रणाली की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण प्रणाली की पुनरीक्षा भी शामिल है। एक जिले में, उसी जिले में वितरण के लिए पोस्ट की गई डाक दूर-दराज के और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित स्थानों को छोड़कर अगले दिन वितरित कर दी जाती है। ऐसी डाक की स्थिति की पिछली पुनरीक्षा अखिल भारतीय डाक सर्वेक्षण, 1994 के दौरान की गई थी।

(ख) पुनरीक्षा के परिणामों से पता चलता है कि जम्मू और कश्मीर के मामले को छोड़कर, सभी सर्किलों में मानदंडों के अनुसार ग्रामीण डाक वितरण का प्रतिशत अच्छा है। 8 सर्किलों में ऐसी डाक की मात्रा का 80 प्रतिशत से भी अधिक अगले दिन वितरित किया गया। 8 अन्य सर्किलों में एक जिले से दूसरे जिले में अगले दिन वितरित की गई डाक का प्रतिशत 58 से 80 के बीच रहा जो जिलों की भौगोलिक स्थिति और ट्रांसपोर्ट कनेक्शन पर निर्भर करता है।

(ग) सभी सर्किलाध्यक्षों को अपने-अपने सर्किलों में डाक और पारेक्षण व्यवस्थाओं को नया रूप देने को कहा गया है, जिसमें शाखा डाकघरों से ज़िले के भीतर और पड़ोसी जिलों में वितरण के लिए तथा पड़ोसी जिलों से जिले में वितरण के लिए आने वाली ग्रामीण डाक पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। इसके परिणामस्वरूप, सर्किलाध्यक्षों ने जिले के भीतर और एक जिले से दूसरे जिले की डाक के लिए पारगमन मानदंड निर्धारित किए हैं और वे डाक के पारेक्षण और वितरण की निरंतर मॉनीटरिंग कर रहे हैं।

Approval to Ordinance Forwarded By Government of Karnataka

1623. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government of Karnataka have forwarded to two ordinances to acquire the Maharaja's Palace at Bangalore and to create Trust for Rocrich Estate at Bangalore approving all the modifications suggested;

(b) if so, by when Government are going to approve the two ordinances; and

(c) if there is delay, the reasons for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) to (c) The Bangalore Palace (Acquisition and Transfer) Ordinance, 1992 was closed as the clarifications sought from the Government of Karnataka were not received in time. The Roerich and Devikarani Roerich State (Acquisition and Transfer) Ordinance, 1995 was received in this Ministry on 5.1.1995. The State Legislations call for their examination by the concerned Department/ Ministeries of the Government of India and consultations with the State Government, wherever necessary. There has been no delay in the matter.

Increase in the target of freight loading

1624. SHRI JOBON ROY: will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whther it is a fact that the target of freight loading has increased in current financial year as compared with past five years; and

(b) if so, the number of wagons required by Railways to meet the same target in current financial year and what was the number of wagons used by Railways in the year 1985-86 to 1989-90?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) Yes, Sir.

(b) Procurement of 24,000 B.G. wagons (in terms of four wheeler units) including about 5,000 wagons under "Own Your Wagon Scheme", is planned in the current year.

Figures of holding of wagons (in terms of four-wheeler units) on Indian Railways in different years is as under:

Year	Holding of BG (FWU)	Holding of MG (FWU) (May figures of following year
1985-86	4,29,552	95514
1986-87	4,32,019	90721
1987-88	4,34,727	86843
1988-89	4,47,637	83605
1989-90	4,67,109	84873

शाखा डाकघर खोलने हेतु निर्धारित लक्ष्य

1625. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले जाने वाले शाखा डाकघरों की संख्या के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) 30 जून 1995 की तिथि के अनुसार प्राप्त किये गये लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान डाकघर खोलने के लिए डाक सर्किल-वार निर्धारित संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। नीचे देखिए योजना लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1996-97 के लक्ष्य को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) 30, जून, 1995 की स्थिति के अनुसार लक्ष्यों का सर्किल-वार ब्यौरा विवरण-'' में दिया गया है।

विवरण-I

आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों (1992-93, 1993-94, 1994-95 और 1995-96) के दौरान शाखा डाकघर खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा।

क्र.सं.	सर्किल का नाम	डाकघरों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	40
2.	असम	61
3.	बिहार	173
4.	दिल्ली	-
5.	गुजरात	54
6.	हरियाणा	24
7.	हिमाचल प्रदेश	49
8.	जम्मू और कश्मीर	10